बजट 2022-23 की प्रमुख विशेषताएं

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार का बजट 2022-23	**-**	**₹75,800 करोड़**
बजट योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं	**-**	**₹43,600 करोड़**
स्थापना बजट	**-**	**₹32,200 करोड़**
राजस्व मद के अंतर्गत बजट	**-**	**₹53,687 करोड़**
पूंजी मद के अंतर्गत बजट	**-**	**₹22,113 करोड़**

- 2022-23 में बजट अनुमान 75,800 करोड़ रुपये है, जो 2021-22 में 69,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 9.86% अधिक है और 2021-22 में 67,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 13.13% अधिक है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान 75,800 करोड़ रुपये का बजट मुख्य रूप से स्वयं के संसाधनों से वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है। प्रमुख घटकों में स्वयं के कर राजस्व से 47,700 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व से 1000 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 325 करोड़ रुपये, लघु बचत ऋण से 10,000 करोड़ रुपये, 802 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां, 10,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा, केंद्र प्रायोजित योजना के लिए 1621 करोड़ रुपये, भारत सरकार से अनुदान सहायता / सामान्य सहायता के रूप में 643 करोड़ रुपये। ।

दिल्ली की अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण दिल्ली की जीएसडीपी में मौजूदा कीमतों पर 1.09 प्रतिशत और स्थिर कीमतों पर 3.86 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि, अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था मौजूदा कीमतों पर 17.65 प्रतिशत और स्थिर कीमतों पर 10.23 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है।
- दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय रु. 2021-22 में मौजूदा कीमतों पर 4,01,982 रुपये है जो देश में तीसरी सबसे ज्यादा है। यह राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1,49,848 रुपये से 2.7 गुना अधिक है।
- लेनदेन के माध्यम से दिल्ली में प्रति व्यक्ति व्यय 2015-16 में 19,218 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 35,763 रुपये होने की संभावना है ।

रोज़गार बजट

- दिल्ली सरकार अपने "रोज़गार बजट" में दिल्ली के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और पिछले कुछ वर्षों में कोविड -19, GST और डेमॉनिटाईज़ेशन के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबरने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- अगले पांच वर्षों में दिल्ली की कामकाजी आबादी के प्रतिशत को 33% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य। अगले 5 साल में दिल्ली में 20 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।
- नए रोजगार सृजित करने के लिए खुदरा क्षेत्र, खाद्य और पेय पदार्थ, रसद और आपूर्ति श्रृंखला, यात्रा और पर्यटन, मनोरंजन, निर्माण, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीएस सूचना और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई है।
- रोजगार सृजन पर केंद्रित नीतियों को लागू करने के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 4,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

महत्वपूर्ण योजनाएं

खुदरा और थोक

- **खुदरा बाजारों का संवर्धन और नवीनीकरण:** अगले 5 वर्षों में दिल्ली के पारंपरिक प्रतिष्ठित बाजारों के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के पुनर्विकास के लिए 2022-23 में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- **दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल:** "दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल" के आयोजन के लिए ₹ 250 करोड़ आवंटित किए गए है ।"**दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल**" का आयोजन हमारे देश के साथ-साथ बाकी दुनिया के लोगों को दिल्ली में खरीदारी करने और इसे एक त्योहार के रूप में अनुभव करने के लिए प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किया जाएगा। फेस्टिवल के दौरान खरीदारों को आकर्षक छूट दी जाएगी। उत्सव में तीन मुख्य आकर्षण होंगे - खरीदारी, मनोरंजन और भोजन। हमारी सरकार विक्रेताओं (दुकानदारों, रेस्तरां मालिकों और उद्यमियों) को एसजीएसटी रिफंड देकर छूट देने के लिए प्रेरित करेगी। इससे इन क्षेत्रों में कार्यरत 12 लाख लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे व्यापार में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल**: दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के हिस्से के रूप में, दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल में थोक व्यापारियों को भी शामिल करा जायेगा और थोक ग्राहकों के लिए आकर्षक छूट की भी योजना है।
- व्यापारियों के लिए "शून्य सेटअप लागत" पर दुकानदारों और खुदरा बाजारों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल – "**दिल्ली बाजार**" विकसित किया जाएगा । इस योजना के तहत 20 करोड़

रुपये प्रस्तावित है, जिससे दिल्ली में 10 लाख विक्रेताओं को लाभ होने की उम्मीद है। इससे अगले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर खुदरा क्षेत्र में निर्मित होने की उम्मीद है ।

- **गांधीनगर के रेडीमेड गारमेंट बाजार को 'ग्रैंड गारमेंट हब' के रूप में विकसित करना।** इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में 40,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

उद्यमिता मानसिकता

- **बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम** के तहत दिल्ली सरकार के स्कूलों के 11वीं और 12वीं कक्षा के 03 लाख से अधिक छात्रों ने 51,000 व्यावसायिक विचारों पर सफलतापूर्वक काम किया और हजारों व्यावसायिक विचार उत्पन्न किए जिन पर ये बच्चे लगातार काम कर रहे हैं। बिजनेस ब्लास्टर्स योजना का विस्तार सरकारी स्कूलों के अलावा निजी स्कूलों में भी किया जाएगा।
- दिल्ली भारत की स्टार्ट-अप राजधानी है। सरकार दिल्ली में **स्टार्ट-अप की स्थापना** की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 'स्टार्ट-अप' नीति तैयार की है। इस प्रक्रिया में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना, मार्केटिंग के लिए सम्मेलन आयोजित करना, सलाह और निवेश करना, उद्यमियों को बैंकों और निवेशकों से जोड़ना शामिल है। बजट अनुमान 2022-23 में 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

यात्रा व पर्यटन

- दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने और दिल्ली को एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म गंतव्य के रूप में ब्रांड करने के लिए - **दिल्ली फिल्म नीति** लागू होगी । 25 से अधिक हितधारक एजेंसियों के साथ फास्ट-ट्रैक अनुमोदन के लिए एक ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म (ई-फिल्म क्लीयरेंस) का निर्माण किया जाएगा ।
- खाद्य और पेय उद्योग के व्यापारियों और कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए चार नई नीतियां शुरू करी जाएगी । **फ़ूड ट्रक नीति** की शुरुआत से फ़ूड ट्रक शहर में विभिन्न स्थानों और समय पर चल सकेंगे, जिससे दिल्ली की रात के समय की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये अगले पांच वर्षों में 60 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।
- बजट 2022-23 में **क्लाउड किचन** को प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ भूमि प्रदान करना, लाइसेंसिंग प्रक्रिया और नियमों को आसान बनाना। क्लाउड किचन में राजस्व सृजन की अपार संभावनाएं हैं, यह क्षेत्र बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करता है। इसमें अगले 5 वर्षों के भीतर 42,000 नए रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है।

औद्योगिक विकास

- बापरोला में **दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक सिटी** को 90 एकड़ के प्लग एंड प्ले निर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली के साथ-साथ देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को दिल्ली में अपना आधार स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- अगले पांच वर्षों में **25 अधिसूचित गैर-अनुरूप** औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाएगा। यह दिल्ली के लोगों के लिए रोजगार के 6 लाख से अधिक नए अवसर पैदा करेगा।

ग्रीन जॉब्स

- भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार के 2047 के दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है। अगले पांच वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा कई हरित पहलों के शुभारंभ के साथ **एक लाख हरित रोजगार** सृजित किए जाएंगे।
- दिल्ली सरकार आने वाले वर्ष में महिला ड्राइवरों के लिए 33% आरक्षण के साथ 4200 ई-ऑटो लॉन्च करेगी। अगले पांच वर्षों के लिए हर साल 5000 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे और इससे 25,000 नए रोजगार पैदा होंगे ।
- रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापित क्षमता को 2500 मेगावाट (पीक) तक ले जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2022-23 में एक नई सौर नीति पेश की जाएगी। यह इस क्षेत्र में बिक्री, निर्माण श्रमिकों, इलेक्ट्रीशियन, तकनीशियनों और इंजीनियरों के लिए **40,000 नौकरियां पैदा** करेगा।

महिला केंद्रित नीतियां

- दिल्ली के हरित आवरण को बढ़ाने, पौष्टिक जैविक भोजन की आपूर्ति और घर पर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में IARI (पूसा संस्थान) के सहयोग से **'स्मार्ट अर्बन फार्मिंग'** शुरू करेगी। इससे अगले पांच वर्षों में दिल्ली में 25,000 नए रोजगार पैदा होंगे ।

रोज़गार बाज़ार

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक कृत्रिम बुद्धि-आधारित वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन, **रोज़गार बाज़ार 2.0** विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिल्ली के युवाओं और विशेष रूप से महिलाओं को हर साल कम से कम 1 लाख नौकरियां प्रदान करना है।

सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी

- सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी: दिल्ली में लगभग 100 विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं के लिए अब तक 4.11 लाख लोग इस सुविधा का उपयोग कर चुके हैं। इस सेवा को 300 प्रकार की सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

शिक्षा

- दिल्ली सरकार के स्कूलों ने अब तक COVID-19 महामारी के बावजूद सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए हैं और लगभग असंभव माने जाने वाले सौ प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत परिणाम (99.84%) हासिल किए हैं।
- स्कूल विज्ञान संग्रहालय के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बेघर बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों की कक्षाओं को अगले 4 वर्षों में डिजिटल कक्षाओं में बदल दिया जाएगा।
- दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय ने भी अपना काम शुरू कर दिया है और भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अगले सत्र से बी.एड पाठ्यक्रम प्रदान करने जा रहा है।

स्वास्थ्य

- दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू किये है। वर्तमान में, ये क्लीनिक 20 स्कूलों में पायलट आधार पर खोले गए हैं और प्रत्येक बच्चे की हर 6 महीने में योग्य डॉक्टरों और नर्सों द्वारा पूर्ण जांच की जाती है।
- 4 नए अस्पतालों के निर्माण और 15 मौजूदा सरकारी अस्पतालों के रीमॉडलिंग के लिए 1900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बिस्तरों की क्षमता में 16000 बिस्तरों की वृद्धि हो जाएगी
- मौजूदा औषधालयों को अपग्रेड करने और आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या को 1000 तक बढ़ाने के लिए, 2022-23 के बजट में 475 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत के बाद से अब तक 5.49 करोड़ रोगियों ने मोहल्ला क्लीनिक की सेवाओं का लाभ उठाया है।
- दिल्ली आरोग्य कोष योजना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली और स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए 160 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

❖ दिल्ली सरकार के डीपीएसआरयू में "सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योग साइंस" में प्रशिक्षित 450 योग शिक्षक प्रतिदिन 15,000 से अधिक लोगों को योग सिखा रहे हैं। आम आदमी योगशाला के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
❖ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9769 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान। इसमें 7522 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 2247 करोड़ रुपये का पूंजीगत बजट शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

❖ दिल्ली ऐसा पहला राज्य बना जहां COVID-19 के कारण मरने वाले व्यक्ति के परिवार को ₹ 50,000 की तत्काल सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत 27,322 परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की गई है।
❖ वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, विकलांग और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत 3,063 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट अनुमान 2022-23 में किया गया है। 8.5 लाख हितग्राहियों को 2000 से 2500 रुपये की पेंशन प्रति माह प्रदान की जा रही है।
❖ "जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना" के तहत 13136 छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत बजट अनुमान 2022-23 में 160 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, इससे वित्तीय वर्ष 2022-23 में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी।

आवास और शहरी विकास

❖ सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाने सहित सड़कों, सीवरों, पार्कों आदि का निर्माण कार्य इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लिया गया है, बजट अनुमान 2022-23 में अनधिकृत कॉलोनियों में निर्माण कार्यों के लिए 1,300 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
❖ वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में आवास एवं शहरी विकास योजनाओं के लिए 5766 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

❖ दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में शत-प्रतिशत सीवर मुहैया कराने का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।
❖ स्वच्छ यमुना अभियान आगे बढ़ रहा है और दिल्ली में यमुना 2 साल में पूरी तरह से साफ हो जाएगी।
❖ सीवेज और सीवरेज के उपचारित जल के उपयोग की नीति लागू की गई है। यह ट्रीटेड पानी हरित पट्टी, जंगल, फार्म हाउस और बागवानी के लिए दिया जाएगा।

❖ नजफगढ़ नाला जो पहले साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था, जो अब गंदे पानी के कारण नजफगढ़ नाले के रूप में पहचाना जाता है, को साफ करके और इसके दोनों ओर की सड़कों को सुंदर बनाकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

सड़क अवसंरचना

❖ 5 पुलों, 2 अंडरपास, एक पैदल यात्री सबवे और आश्रम तक डीएनडी फ्लाईवे के विस्तार का काम 2022-23 में पूरा किया जाएगा। इससे त्रिनगर, इंद्रलोक, करमपुरा, रामपुरा, नांगलोई, बसई दारापुर, कोंडली और आश्रम चौक पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

❖ सरकार पहले ही दिल्ली के नागरिकों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 11,000 मुफ्त वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित कर चुकी है। औसतन 4.1 लाख लोग प्रतिदिन इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

❖ स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में, दिल्ली में 500 राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना के कार्यकर्म के अंतर्गत, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 175 राष्ट्रीय ध्वज पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और शेष कार्य अगस्त 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

परिवहन

❖ परिवहन विभाग ने एक बड़ी पहल के तहत फेसलेस सिस्टम में 47 सेवाएं शुरू की हैं। नए वाहन के लिए अपनी आरसी प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वाहन डीलर द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके अलावा, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से लोग अपना लर्नर लाइसेंस घर से बनवा सकते हैं। 7 मार्च, 2022 तक 11 लाख से अधिक आवेदक इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं।

❖ महिलाओं को डीटीसी एवं क्लस्टर बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की सुविधा को जारी रखने के लिए बजट अनुमान 2022-23 में 250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

❖ दिल्ली में बसों की संख्या 7,003 तक पहुंच गई है जो दिल्ली के इतिहास में बस बेड़े की सबसे बड़ी संख्या है।

❖ परिवहन, सड़कों और पुलों के लिए बजट अनुमान 2022-23 में 9,539 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

पर्यावरण और वन

❖ "दस सूत्रीय - शीतकालीन वायु कार्य योजना (Ten Point - Winter Air Action Plan)" 1 अक्टूबर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक सक्रिय किया गया । जिसके तहत पराली जलाने पर नियंत्रण, धूल-विरोधी अभियान, कचरा जलाने की रोकथाम, आतिशबाजी पर प्रतिबंध, स्मॉग टॉवर की स्थापना, अधिक प्रदूषण

फैलाने वाले स्थलों की पहचान, ग्रीन वॉर रूम को मजबूत करना, ई-कचरा पार्क की व्यवस्था और वाहन प्रदूषण नियंत्रण के उपाय शामिल हैं ।

- दिल्ली में वन और वृक्ष आच्छादन 2019 में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.88% से बढ़कर 2021 में 23.06% हो गया है। सात प्रमुख मेगा शहरों के मुक़ाबले में, दिल्ली में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो लगभग 194 वर्ग किमी को कवर करता है।
- पिछले दो वर्षों में 11 शहरी वनों का विकास किया गया है जो तेजी से बढ़ते शहरी कंक्रीट क्षेत्रों में हरित स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के जानवरों के इलाज के लिए दिल्ली का पहला "सरकारी पशु चिकित्सा कॉलेज" स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

ऊर्जा

- 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए "शून्य बिजली बिल योजना" बहुत सफल रही है जो ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। सरकार 1984 के दंगों के पीड़ितों को 400 यूनिट तक बिजली की खपत के लिए 100% सब्सिडी भी दे रही है। बिजली सब्सिडी योजना को अदालत परिसर के भीतर वकीलों के कक्षों तक भी बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत 3250 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट अनुमान 2022-23 में प्रस्तावित किया गया है।
- बजट अनुमान 2022-23 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3,340 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

श्रम

- COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से निर्माण श्रमिकों की दुर्दशा को समझते हुए, दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया और लगभग 500 करोड़ रुपये की सहायता 5 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के खाते में प्रदान की ।

*****